Selling of confiscated Gold

96. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether in view of the Chelliah Committee's recommendations, Government have decided to sell the gold confiscated and seized by various enforcement agencies like customs from smugglers and others by way of auction and to use the amount so raised alongwith the amount raised by way of disinvestment of public sector shares in clearing the public debts and raising the RBI dividends;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the amount of domestic public debt as at the end of 1991-92 and the extent of confiscated gold as available on 1st April, 1992 and at present?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) No, Sir.

(c) The amount of internal public debt and other liabilities of the Central Government at the end of 1991-92 (RE) stood at Rs. 3,17,379 crores. The quantity of confiscated gold held in Government accont as on 1.4.1992 and 19.11.1992 was 186.8 kg. and 1,071 kg. respectively.

बैंक कर्मियों की छंटनी

97. **श्री राम नरेश यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय या आई०बी०ए० (बम्बई) के पास बैंक-कर्मियों की छंटनी करने सम्बन्धी कोई योजना लम्बित है जैसा कि दिनांक 26 सितम्बर, 1992 के दैनिक "राष्ट्रीय सहारा" (दिल्ली संस्करण) में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो "एक लाख कर्मियों की छंटनी" सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस योजना के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली संभावित बेरोजगारी की समस्या के सम्बंध में कोई अध्ययन कराया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। बैंक कर्मचारियों की छंटनी के सम्बन्ध में कोई योजना लम्बित नहीं है। तथापि, भारतीय बैंक संघ, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों की स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के लिए एक योजना की सम्भावना तथा प्रासंगिकता की जांच कर रहा है।

(ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में बैंकों का विलय

98. **श्री राम नरेश यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली से प्रकाशित 29 अगस्त, 1992 के दैनिक "इकानामिक टाइम्स" (अंग्रेजी) में "एस०बी०आई० एसोसिएट बैंक्स फार मरजर विद स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद" शीर्षक से प्रकाशित हुए एक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो विलय के मामले में सरकार के विचार क्या हैं; और

(ग) सभी सहयोगी बैंकों का विलय कब तक किया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने इस प्रस्ताव पर भारतीय रिजर्व बैंक के विचार मांगे हैं। इस स्तर पर, प्रस्ताव पर निर्णय लेने सम्बन्धी किसी समय सीमा को बताना सम्भव नहीं होगा।

ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्र के निवेशकों को शेयरों में निवेश के लिए प्रोत्साहन देने की योजना

99. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के निवेशकों को शेयरों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने की कोई योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, नहीं। सरकार, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के निवेशकों को शेयरों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोई योजना नहीं बना रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Proposal to Scrap Expenditure tax on Foreign Tourists

100. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to scrap expenditure tax on foreign tourists;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) There is no proposal under Government's consideration to scrap expenditure tax on foreign tourists at present.

(b) In view of the answer at (a) above, it does not arise.

(c) In view of the adjustment in exchange rates the exemption to expenditure incurred, or the payment for which is made, in foreign-exchange, has been withdrawn with effect from the 1st day of October, 1992. Hence, there is no proposal at present under the Government's consideration to scrap expenditure tax on foreign tourists.

चांदी का आयात

101. **डा० बापू कालदाते**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार चांदी का आयात करने के लिए उसी प्रकार अनुमति देने पर विचार कर रही है जिस प्रकार उसने सोने का आयात करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो चांदी के आयात के संबंध में सरकार अन्तिम निर्णय कब तक लेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

102. **डा० बापू कालदाते**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अपने कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितने कर्मचारियों को बोनस का लाभ प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान वेतन और भत्तों में तो वृद्धि हुई है परंतु बोनस के भुगतान की वेतन-सीमा को बढ़ाया नहीं गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार बोनस के लिए रखी गई वेतन सीमा को समाप्त करके सभी कर्मचारियों को समान बोनस देने का विचार रखती है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे): (क) जी, हां।

(ख) भिन्न-भिन्न बोनस स्कीमों के तहत लाभ पाने वालों की संख्या सम्बंधी सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है।

(ग) बोनस के लिए पात्रता सीमा बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के उपबंधों से सम्बद्ध है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

घरेलू और विदेशी ऋणों की सीमा

103. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू और विदेशी ऋण की सीमा बांधने के प्रश्न पर कोई फैसला लिया है;

(ख) राज्यों को संसाधनों के हस्तान्तरण के संबंध में कौन-कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं; और

(ग) सरकार ने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए क्या उपाय किए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे): (क) सरकारी ऋणों पर सांविधिक अधिकतम सीमा लगाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) राज्यों को संसाधनों का अन्तरण वित्त आयोग की सिफारिशों, योजना आयोग द्वारा यथा-अनुमोदित राज्य योजनाओं के वित्त पोषण की स्कीम और विभिन्न आयोजना-भिन्न और राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रयोजित स्कीमों के संबंध में आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है।